पाँचवा-स्तम्भ

25 years CUTS International 1983 2008

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 12, अंक 4/2011

...भूख का इलाज-खाद्य सुरक्षा?

दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल देकर केन्द्र सरकार देश के करोड़ों गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने की बात कर रही है। इस मकसद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 बनाया गया है। इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसे संसद के पटल पर रखा गया है जिस पर बहस होना बाकी है।

भूख के इलाज के लिए यह विधेयक कब और कैसे लागू होगा? इससे क्या वास्तविक जरुरतमंद लोग लाभान्वित हो सकेंगे? अन्य योजनाओं की तरह क्या यह भी भ्रष्टाचार का माध्यम नहीं बनेंगी? ऐसे कई सवालों को किस तरह सुलझाया जाएगा, अभी स्पष्ट नहीं हैं। अभी तक तो यह भी तय नहीं हो पाया कि योजना के लाभ किस वर्ग और श्रेणी को मिलेंगे। क्योंकि, गरीबों और जरूरतमंदों की पहचान अभी होनी बाकी है। पिछले दिनों गरीबी रेखा के लिए 32 या 26 रुपए रोज की आय में गुजर-बसर के मानदण्ड ने सरकार की कैसी फजीयत कराई है, वह हम देख चुके हैं।

खासतौर से विचारणीय मुद्दा यह है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल सस्ता अनाज उपलब्ध कराना ही नहीं है, इसमें सभी खाद्य वस्तुओं का उत्पादन, गुणवत्ता, पोषकता, पर्याप्त उपलब्धता व उनके भंडारण की व्यवस्था के साथ-साथ उनके समुचित वितरण और उसकी निगरानी भी सम्मिलित हैं।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए हो रही लचर वितरण व्यवस्था में व्याप्त कालाबाजारी और इसके माध्यम से हो रही लूट किसी से छिपी नहीं है। इससे खाद्य सुरक्षा को जोड़ना तब तक कारगर नहीं माना जा सकता, जब तक इस प्रणाली और व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त कर ईमानदार नहीं बनाया जाता। लोगों का मत यह भी है कि गरीबों को कमाने लायक और उत्पादकता से जोड़ने लायक बनाया जाए, जिससे वे जरूरी चीजें खरीदने में सक्षम हो सकें।

इस अंक में...

- सरकार क्यों नहीं करती पहल? 4
- पुलिस और नेता सबसे ज्यादा भ्रष्ट 5
- लोक सेवा गारंटी कानून प्रदेश में लागू 7
- साफ पानी शहर की पहली जरूरत 9
- अपना स्वार्थ नहीं छोड़ रहे विकसित देश 11

उपभोक्ता संरक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाने की आवश्यकता

उपभोक्ताओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि में कानून का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिल जाना चाहिए था। लेकिन इतने वर्ष बाद भी अगर इस कानून की पूरी तरह पालना नहीं हो रही है, तो उपभोक्ता हितार्थ सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा ग्रासरूट स्तर पर भी प्रेशर ग्रुप तैयार करने होंगे।

उक्त विचार वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोडा ने कट्स द्वारा जयपुर में 29 नवम्बर 2011 को आयोजित राज्यस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्यवक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। श्री बोडा ने वर्तमान में खुला बाजार और प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण प्रक्रिया को अधिक मजबूती देने की आवश्यकता जताई। यह सम्मेलन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से कट्स द्वारा राजस्थान के 12 जिलों में संचालित ग्रासरूट रीचआउट एण्ड नेटवर्किंग इन राजस्थान थ्रू कन्ज्यूमर एक्शन (ग्रेनिर्का) परियोजना के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

इससे पूर्व कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि इस साल उपभोक्ता संरक्षण कानून की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, किन्तु अधिकतर उपभोक्ता आज भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ता निदेशालय की शीघ्र स्थापना हो, ताकि उपभोक्ता से सम्बन्धित विभागों को एक छत के नीचे लाया जा सके। इस अवसर पर कट्स द्वारा उपभोक्ता जागरूकता हेतु तैयार किए गए पोस्टरों का विमोचन भी किया गया।

सम्मेलन में डॉ.पूनम पाण्डे, परियोजना एसोसिएट, जी.आई.जेड. नई दिल्ली ने उपभोक्ता सलाहकार नेटवर्क और जी.आई.जेड.द्वारा तैयार किए गए सूचना प्रौद्योगिकी मंच के बारे में बताया। उन्होंने प्रजेन्टेशन के माध्यम से बताया कि मंच किस प्रकार देशभर के उपभोक्ताओं को सलाह और परामर्श दे रहा है।

कट्स के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना ने उक्त परियोजना के तहत दो वर्षों की गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण करते हुए फील्ड सर्वे से प्राप्त निष्कर्षों और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 12 जिलों के परियोजना सहयोगी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं मीडिया प्रतिनिधियों सहित 60 से भी अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

ऊर्जा कुशल उत्पादों से संभव है बिजली की बचत

प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और इसके विपरीत उत्पादन की कमी के कारण शहरों में आए दिन बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। बिजली कंपनियां बिजली की चोरी और छीजत पर भी पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाई। बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे और इससे होने वाली बिजली दरों में बढ़ोतरी का नुकसान आमजन को भुगतना पड़ता है। मद्देनजर विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षण उत्पादों का उपयोग कर बिजली की बचत करनी चाहिए। इसके साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देना होगा।

उक्त विचार कट्स द्वारा 24 अक्टूबर 2011 को जयपुर में आयोजित 'सेव टू सर्वाइव'-ऊर्जा कुशल उत्पादों पर अभियान से जुड़ी विचार विमर्श बैठक में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के संयुक्त सचिव आर.सी.शर्मा ने व्यक्त किए। बैठक का आयोजन स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन के सहयोग से किया गया था।

इससे पूर्व कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने ऊर्जा संचयन व ऊर्जा कुशल उत्पादों के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को बताया कि ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों के उपयोग से कम लागत आती है, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक लाभ होता है। ऊर्जा संरक्षण प्रयासों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। हालांकि सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन बढ़ती मांग के अनुरूप बेहतर प्रबन्धन व ऊर्जा संरक्षण से मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम किया जा सकता है।

बैठक में उपस्थित राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम के परियोजना प्रबंधक सुमित माथुर ने बताया कि आज के युग में ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को भी बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है। इसके लिए प्रदेश में पवन व सौर ऊर्जा को तवज्जो दी जा रही है विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में भी वैकल्पिक ऊर्जा और स्टार रेटिंग पंप सेट्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैठक में जयपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता एस. के. राजपूत ने अपशिष्ट पदार्थों से बिजली उत्पादन पर प्रकाश डाला। बैठक में 70 से भी अधिक सरकारी अधिकारियों, मीडिया और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारत सहित आठ देशों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बांटे अपने अनुभव

पार्टनरशिप फॉर ट्रांसपेरेन्सी फण्ड (पी.टी.एफ.) ने 'कट्स' के साथ मिलकर 29 नवम्बर से 02 दिसम्बर, 2011 तक चार दिवसीय 'एशिया -रीजनल पियर लर्निंग एण्ड नॉलेज शेयरिंग' कार्यशाला का जयपुर में आयोजन किया। कार्यशाला में पी.टी.एफ.के एशिया पार्टनर्स ने भाग लिया जो कि मंगोलिया, फिलिपीन्स, करकिजस्तान, अफगानिस्तान, भारत एवं नेपाल से आये थे।

कार्यशाला में आठ देशों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं व विश्व बैंक के प्रतिनिधियों सहित 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का खास मकसद पी.टी.एफ. के सभी सहभागियों को एक मंच पर लाना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध विषय विशेषज्ञों द्वारा अर्जित अनुभवों को आपस में बांटना, कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं के निदान के सुझावों पर विचार-विमर्श एवं मंथन कर एक प्रभावी नेटवर्क तैयार करना था।

कार्यशाला में 30 'केस स्टडीज' प्रस्तुत की गई तथा भ्रष्टाचार, सुशासन व जवाबदेहिता की कार्यप्रणालियों द्वारा सरकारी तंत्र में सुधार हेतु किये गये प्रयोगों को आपस में बांटा गया, जिससे कि प्रतिभागी अपने-अपने क्षेत्रों में इनका प्रयोग कर आवश्यक सुधार कर सकें। 'कट्स' की तरफ से जॉर्ज चेरियन ने सभी का स्वागत करते हुए सुशासन व जवाबदेही पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार व्यक्त किए। कार्यशाला का संचालन एवं प्रबन्धन मधुसूदन शर्मा ने किया और अपने अनुभवों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

'सामुदायिक जनित अंक पत्र' प्रणाली का ग्राम पंचायतों में प्रयोग

सुशासन एवं जवाबदेही हेतु 'कट्स' द्वारा संचालित परियोजना के अन्तर्गत राज्य में 66 भागीदार सहभागी संस्थाओं को सामाजिक जवाबदेही के एक उपकरण 'सामुदायिक जनित अंक-पत्र' पर प्रशिक्षण दिया गया था। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी संस्थाएं अपने सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में 'सामुदायिक जनित अंक-पत्र' प्रणाली का क्रियान्वयन कर रही है।

गत तीन महीनों के दौरान सहभागी संस्थाओं द्वारा कुल 51 ग्राम पंचायतों में इस प्रणाली का प्रयोग किया जा चुका है। उक्त प्रक्रिया के माध्यम से समुदाय और सेवा प्रदाता के मध्य पारदर्शिता को बढ़ाने और संवादहीनता को कम करने में सहायता मिलती है। परियोजना के तहत समुदाय जनित अंक प्रक्रिया का उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा)के कार्यक्रमों पर किया जा रहा है, जिससे कई सुधारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की करतूत

करे कोई भरे कोई ... कहावत वित्त, गृह व न्याय विभाग सहित एक दर्जन सरकारी महकमों पर खरी उतर रही है। इन विभागों ने निर्माण कार्यों के पेटे सार्वजनिक निर्माण विभाग को 2722 करोड़ रुपए दिए लेकिन इनमें से 1123 करोड़ रुपए उसने अपनी तिजोरी में रख लिए। यह पैसा देने पर भी काम नहीं होने से इन विभागों के विकास का ग्राफ नीचे दिखने लगा है।

विभागों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को 5-6 सालों से निर्माण कार्यों का पैसा तो पूरा दिया जा रहा है लेकिन काम आधा अधूरा हो रहा है। इससे इन विभागों को सरकार की फटकार झेलनी पड़ती है। विभाग के आंकड़े सामने आने पर पाया गया कि थाना भवन, आदिवासी इलाकों में छात्रावास, आवासीय स्कूल, अस्पताल निर्माण जैसे कई काम पूरे नहीं हो रहे हैं। *(रा.प., 01.12.11)*

किसानों की सब्सिडी खा गए अफसर

केन्द्र सरकार के भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.(एसएफसीआई) की ओर से बीज उत्पादन कार्यक्रम में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। प्रदेश में बीज उत्पादन के बदले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को हड़पने के लिए अफसरों ने फर्जी कागजात तैयार किए और 1 करोड़ 70 लाख रुपए खुर्द-बुर्द कर दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ी निगम के किशनगढ़ रेनवाल यूनिट में सामने आई।

जांच में सामने आया कि यहां 100 किसानों से चना और 29 किसानों से गेहूं का बीज उत्पादन करना बताया। कागजों में यह उत्पादन दिखा कर अधिकारियों ने सब्सिडी की 80 फीसदी राशि एक करोड़ 70 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान दिखा दिया। जबकि असल में यह राशि किसानों तक पहुंची ही नहीं। जांच कमेटी की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भी भिजवाई गयी। केन्द्र ने बीज उत्पादन कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और सब्सिडी राशि की वसूली के आदेश दिए हैं।

(दै.भा., 06.12.11 एवं 08.12.11)

आमदनी बढ़ी फिर खर्च में कंजूसी क्यों?

सरकारी खजाने में आमदनी बढ़ने से राजस्व लाभ की स्थिति बन गई, लेकिन राज्य सरकार इसे खर्च करने में कंजूसी बरत रही है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती पांच माह में सरकारी खजाने में पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 5000 करोड़ रुपए ज्यादा आए हैं और राजकोषीय व राजस्व लाभ की स्थिति बन गई है।

दूसरी ओर मॉनिटरिंग के अभाव व सुस्त प्रशासन के कारण लगता है कि सरकार खर्च में कंजूसी बरत रही है। राज्य की 28461.38 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना में से जुलाई तक सिर्फ 21 प्रतिशत राशि अर्थात 6149 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें भी विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम में एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर मात्र 3 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है। विदेशी सहायता परियोजनाओं पर माह अगस्त तक मात्र 22 फीसदी ही खर्च हुआ है। इसमें भी राजस्थान में गरीबी हटाने की 24 करोड़ रुपए की एम्पावर योजना में से केवल डेढ़ करोड़ रुपए खर्च हो सके हैं।

(रा.प., 10.10.11)

भीलवाड़ा डेयरी में जमकर हुए घोटाले

भीलवाड़ा डेयरी में कई सालों से जमकर घपले होते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से सरकार का पैसा राजकोष में नहीं पहुंचा। भीलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष रहे खान मंत्री रामलाल जाट से उनके कार्यकाल का हिसाब खंगालने की सरकार में लम्बे समय तक किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि., जयपुर ने घपलों की जांच बिठाई तो सामने आया कि वर्ष 2001 से 2007 तक भीलवाड़ा डेयरी में कई घपलों को अंजाम दिया गया है। इनमें काफी अनियमितताएं भी मिली। जांच रिपोर्ट में इन अनयमितताओं और घोटालों का वर्षवार ब्योरा दिया गया है। *(रा.प., 16.11.11)*

बीरबल की खिचड़ी बना 'मिड-डे-मील'

सरकारी स्कूलों में बच्चों को गर्म खाना उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की योजना प्रदेश में बीरबल की खिचड़ी बन कर रह गई। केन्द्र ने जिला परिषद, जयपुर को डेढ़ साल पहले 1.63 करोड़ रुपए जारी किए थे। इस राशि से 150 स्कूलों के लिए गैस कनेक्शन, पाइप व चूल्हे और 2000 स्कूलों के लिए हॉट केस, अनाज की टंकी व बर्तन आदि खरीदे जाने थे।

इसके लिए जिला परिषद ने दो बार निविदाएं मांगी और उन पर लाखों रुपए का खर्चा तो कर दिया पर हुआ कुछ भी नहीं। एकल निविदा आने के कारण टैंडर एक बार तो राज्य सरकार के स्तर पर निरस्त हो गया। दूसरी बार निविदा की अवधि पूरी होने के कारण कार्यादेश जारी नहीं हुआ। अब तीसरी बार निविदाए मांगी जाने की तैयारी है।

अगर ब्लॉक स्तर पर स्कूलों को चयन कर उन्हें सीधे सामान खरीदने की अनुमति दी जाती तो छात्रों को इसका जल्दी फायदा मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। *(रा.प., 17.10.11)*

एपीएल के आटे को बाजार में बेचा

आम आदमी के लिए आंवटित सरकारी आटे में घोटाले का 'घुन' लग गया। आटे की आपूर्ति करने वाली फर्म ने रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक सुशीला गोदारा के साथ मिलीभगत कर न सिर्फ एपीएल परिवारों के साथ धोखेबाजी की, बल्कि उनके हक का लाखों रुपए का आटा खुले बाजार में बेच दिया।

प्रारम्भिक पड़ताल में फतेहपुर क्षेत्र में पिछले एक माह में ही करीब तीस लाख रुपए से ज्यादा के आटे की कालाबाजारी सामने आई है। यह तो महज एक उपखण्ड क्षेत्र की बानगी है, सीकर जिले के छह उपखण्डों में भी ऐसी ही गड़बड़ी सामने आ रही है जिसमें यह आंकड़ा करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। अब जिला रसद अधिकारी ने घपले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने की पेशकश की है। *(रा.प., 22.12.11)*

1200 करोड़ का दाल घोटाला

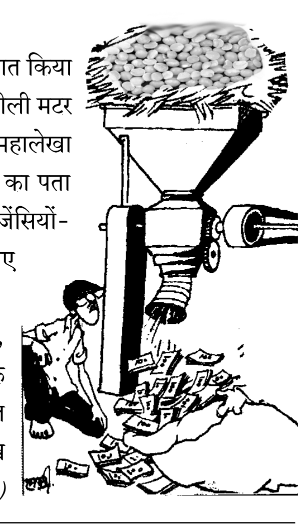

देश में दालों की कमी दूर करने के लिए विदेशों से दालों का आयात किया जाना मिलीभगत का खेल नजर आ रहा है। जरूरत नहीं होने पर भी पीली मटर दाल के आयात का मामला प्रश्न वाचक चिन्ह लगाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस खेल में करीब 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का पता लगाया है। संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी एजेंसियों- एमएमटीसी, एसटीसी, नेफेड तथा पीईसी ने करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शरद पंवार के नेतृत्व वाला उपभोक्ता, खाद्य व पीडीएस मंत्रालय आयातित दालों के वितरण के लिए उपयुक्त चैनल तक तलाश पाने में विफल रहा। इन एजेंसियों ने स्टॉक को सीमित टेंडर के जरिए निपटा दिया और चार निजी करोबारियों को 6.08 लाख मीट्रिक टन दालें बेच दी गई। *(रा.प., 29.12.11, 30.12.11)*

सरकार क्यों नहीं करती पहल?

पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद राज्य के खजाने में सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आएंगे। वाणिज्यिक कर विभाग के सूत्रों के अनुसार वैट व अन्य करों से प्राप्त राज्य के कुल राजस्व 12 हजार 700 करोड़ रुपए में से पेट्रोल व डीजल का हिस्सा 29 प्रतिशत होता है, जिसमें डीजल की खपत ज्यादा होती है। सरकार को 3750 करोड़ रुपए सालाना पेट्रोल और डीजल से मिलते हैं।

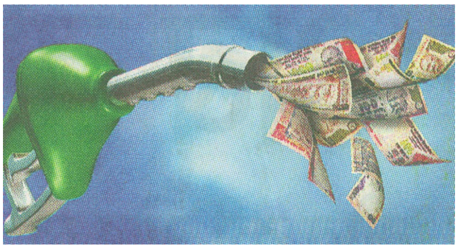

राज्य में पेट्रोल पर 28 प्रतिशत की दर से वैट वसूला जाता है। जबकि हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में वैट की दर क्रमशः 20.5, 20, 22, 22 प्रतिशत है। इन राज्यों में वैट दर कम होने से सस्ती दर का पेट्रोल पूरे प्रदेश में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे प्रदेश को राजस्व की चपत लग रही है। इससे वाकिफ होने के बावजूद राज्य सरकार लोगों को राहत देने में पीछे है और वैट की दर कम नहीं कर रही। *(रा.प., 05.11.11)*

विद्युत थानों में नहीं हुए मामले दर्ज?

बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय विद्युत थाने में उपभोक्ताओं से 'सैटलमेन्ट' किया जा रहा है। रामबाग सर्किल स्थित विद्युत थाने की पड़ताल में यह सामने आया है। जयपुर डिस्कॉम विद्युत वितरण निगम की सतर्कता टीम ने शहरी क्षेत्र में बिजली चोरी करते उपभोक्ताओं को पकड़कर विद्युत थाने में एफआईआर के लिए जनवरी 2011 से अगस्त माह तक 492 जांच प्रतिवेदन भेजे, लेकिन अगस्त तक 90 मामले भी दर्ज नहीं हुए हैं। ऐसे में राजस्व को लाखों रुपए की चपत लगी है।

पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने के बजाय कर्मचारी उपभोक्ताओं से सेटलमेंट कर लेते हैं। इनमें मीटर से छेड़छाड़ करने और लाइन से बिजली चोरी करने के मामले ज्यादा हैं। कई मामले ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरी बार बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इसी प्रकार वर्ष 2009 और 2010 के भी सैकड़ों प्रतिवेदन थाने में धूल फांक रहे हैं जिससे निगम को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। *(दै.भा., 03.10.11)*

छात्रवृत्ति में सामने आया फर्जीवाड़ा

पांचवा स्तम्भ के पिछले अंक में बिना प्रवेश उठा ली छात्रवृत्ति में कर्नाटक के कालेजों में बिना प्रवेश लिए व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति उठाने का मामला प्रकाशित किया गया था। सामने आया है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने करीब 200 छात्रों को एक ही सत्र में दो-दो बार छात्रवृत्ति आवंटित कर दी।

एक सांसद के लड़के के द्वारा तो अपने पिता को मजदूर बताकर लाखों की छात्रवृत्ति उठाने का मामला भी सामने आया। हाल ही आवेदनों की जांच में सामने आया कि छात्रवृत्ति का पैसा पाने के लिए पांच दर्जन से भी ज्यादा छात्रों ने राज्य के बाहर के कॉलेजों में पढ़ना दिखा कर फर्जी रसीद व दस्तावेज के साथ आवेदन कर दिया। जांच मे करोड़ों रुपए के घपले सामने आ रहे हैं। अब प्रशासन सचेत हुआ है व अन्य प्रदेशों में भी विभाग द्वारा जांच की जाएगी। *(दै.भा., 21.10.11, 02.12.11)*

नहीं बांटा, आखिर सड़ गया गेहूं

सरकारी लापरवाही के कारण चित्तौड़गढ़ के तुंबडिया ग्रामसेवा सहकारी समिति (जीएसएस) में पिछले 6 साल से पड़ा 119 क्विंटल गेहूं गरीबों में बांटने के बजाय जमीन में दफन कर दिया गया। यह गेहूं एससीआरवाई योजना के तहत वर्ष 2005 में यहां पहुंचा था। कुछ समय बाद यह योजना बन्द हो गई।

इसके बाद इस गेहूं को मनरेगा में श्रमिकों को वितरण करने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्हें नहीं बांटा गया। इस गेहूं को गरीबों में बांटने के लिए जीएसएस ने कई बार प्रस्ताव भिजवाया लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते यह काम नहीं हुआ। आखिर यह गेहूं सड़ गया और जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहा। पिछले दिनों पीडब्लूडी मंत्री भरत सिह गंगरार में तुंबडिया गांव पहुंचे और उन्होंने इसे जमीन में दफन करने के निर्देश दिए। *(दै.भा., 15.12.11)*

सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान

राज्य की 2009-10 की सीएजी रिपोर्ट में विभिन्न विभागों द्वारा बरती गई बहुतसी अनियमिताओं का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के पैरा संख्या 1.2.1 में बताया गया है कि दिसम्बर 2009 तक 2112.69 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं देखने को मिली थीं, जिसके लिए सीएजी ने संबंधित विभागों को लिखा भी था।

इसके बावजूद विभागों ने अनियमितताओं को नजरअन्दाज किया। रिपोर्ट के पैरा 1.5.1 में बताया गया है कि वर्ष 2009-10 के दौरान 42511 मामलों में करों की कम वसूली और राजस्व नुकसान के कारण राज्य सरकार को 1554.36 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। संबधित विभागों को सीएजी ने इस बारे में जानकारी दी तो विभागों ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है।

रिपोर्ट में जहां वाणिज्य कर विभाग में बरती गई अनियमितताओं का खुलासा किया गया है वहीं भू-राजस्व विभाग की कार्य प्रणालियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। रिपोर्ट में आबकारी विभाग, जल संसाधन विभाग, मोटर वाहन आदि कई विभागों द्वारा की गई राजस्व की कम वसूली को व्यापक रूप से दर्शाया गया है। *(न.ज्यू., 07.10.11)*

गेहूं घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में

सवाई माधोपुर उपभोक्ता होलसेल भंडार में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी कर करोड़ों रुपए के गबन का मामला करीब साल भर से ठंडे बस्ते में दबा है। भंडार में साल भर पहले करीब 17 हजार 805 क्विंटल गेहूं की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ था जिसकी जांच सीआईडी-सीबी भरतपुर को सौंपी गई थी।

मामले में अभी तक ना तो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही गेहूं की रिकवरी के प्रयास किए गए हैं। इस घोटाले के चलते भंडार की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है और कई कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। *(रा.प., 08.11.11)*

गरीबों के हिस्से सिर्फ एक पैसा

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि केन्द्र सरकार एक रुपया गरीबों के लिए भेजती है तो गरीब तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। लेकिन अब हालात यहां तक बदल चुके हैं कि गरीबों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं में उस तक एक रुपए में से सिर्फ एक पैसा ही पहुंच रहा है।

हाल ही देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जीएस सिंघवी और न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने गरीबों की पीड़ा का इजहार करते हुए कहा कि एक रुपए में से एक पैसा ही गरीबों तक पहुंच रहा है। जबकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दलालों व अफसरों को न मिल कर गरीबों को ही मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदू मल्होत्रा को ज्यूरी नियुक्त करते हुए इसके कारणों का पता लगाने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने सभी सरकारी महकमों को कहा है कि वे मल्होत्रा को चाहा गया विवरण मुहैया कराएं। *(रा.प., 04.12.11)*

निजी क्षेत्र में भी रिश्वत लेना जुर्म होगा

गंभीर घोटालों में बड़े घरानों की कथित लिप्तता के खुलासों के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। निजी क्षेत्र में होने वाली रिश्वतखोरी को अपराधिक कृत्य बनाने की गरज से सरकार कानून में बदलाव पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खात्में को प्रतिबद्ध है व इसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सरकारी अधिकारियों के विशेषाधिकार कम करने के तौर तरीके भी तलाशे जा रहे हैं। सार्वजनिक खरीद कानून पर भी काम हो रहा है, ताकि हर साल दिए जाने वाले हजारों करोड़ रुपए के सरकारी ठेकों के आवंटन से जुड़ी अनियमितताएं कम की जा सके। *(रा.प.एवं दै.भा., 22.10.11)*

भ्रष्ट जजों को करें बेनकाब

सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई न्यायाधीश भ्रष्ट है, तो उस न्यायाधीश का नाम सार्वजनिक तौर पर लें और इसके बारे में मुख्य न्यायाधीश को बताएं। उन्होंने लोगों को अगाह किया है कि वे भ्रष्टाचार के कुछ अरोपों को आधार बनाकर सम्पूर्ण न्यायपालिका की छवि धूमिल करने से बचे। कुछ न्यायाधीशों के कारण पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता।

उन्होंने विधि दिवस पर नई दिल्ली में सुप्रीमकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका की ईमानदारी, कार्यकुशलता और उत्कृष्टता को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इससे उसे लोगों का भरोसा बनाए रखने की शक्ति मिलेगी। *(रा.प.एवं दै.भा., 27.11.11)*

भ्रष्ट पुलिस अफसरों की होगी जांच

भ्रष्ट पुलिस अफसरों और कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने विशेष सैल का गठन किया है। ऐसे लोग जो पुलिस के भ्रष्टाचार और दुराचरण से पीड़ित हैं वे इस सेल में शिकायत कर सकते हैं। प्रदेश में इस तरह की सैल पहली बार गठित की गई है। इस सैल की मॉनिटरिंग खुद पुलिस कमिश्नर करेंगे। जांच में मामला सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग से तत्काल हटा दिया जाएगा।

पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी का कहना है कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई हो सके इसके लिए इस सैल का गठन किया गया है। अगर कोई भी पुलिस के व्यवहार से परेशान है या कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो वे उसकी सीधे शिकायत कमिश्नरेट में कर सकते हैं। इसमें सात दिन में जांच पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। बिनचाहे परिवादी का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। *(दै.भा. 03.11.11)*

शासन प्रक्रिया में हो सुधार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि तीव्र गति से प्रगति और विकास के लिए हमारे प्रयासों का पूरा प्रभाव तभी हो सकता है, जब सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर काबू पाए और शासन प्रक्रिया में सुधार लाए। इस दिशा में आगे बढ़ने का यह निर्णायक समय है। राज्यपालों एवं उप राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार लोक प्रशासन में और पारर्शिता लाने तथा लोक प्राधिकरणों में जवाबदेही के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए कानून बना रही है। लोकपाल बिल के साथ-साथ जमीन अधिग्रहण कानून भी संसद में पेश किया जा चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकारें भी इस दिशा मे सख्त कदम उठाएंगी ताकि देश के सभी हिस्सों में हर स्तर के प्रशासन तक इन प्रयासों का असर दिखाई दे। *(दै.भा., 31.10.11)*

लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद रॉय का मानना है कि देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के लिए प्रशासनिक सिस्टम भी दोषी है। सिस्टम में सुधार की जरूरत है। व्यवस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जाना भी भ्रष्टाचार की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है।

उन्होंने पिलानी में पत्रकारों से बातचीत में अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के कारण देश के हालात खराब हैं। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति तभी मिलेगी जब सभी लोग अपने-अपने तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ अवाज उठाएंगे। *(रा.प., 25.11.11)*

पुलिस और नेता सबसे ज्यादा भ्रष्ट

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा सर्वे के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस और नेता सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। लोगों का मानना है कि पुलिस और नेताओं से जल्दी काम कराने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह सर्वे2010 से 2011 के बीच किया गया है।

भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका में भी इसी तरह का सर्वे कराया गया है। इसमें नौ सार्वजनिक सेवाओं- पुलिस, न्यायपालिका, टैक्स राजस्व, सुविधाएं, शिक्षा आदि के बारे में लोगों से राय ली गई। अधिकांश भारतीयों का मानना है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मजबूत लोकपाल बहुत जरूरी है। लोगों का यह भी मानना है कि भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मीडिया का रोल सर्वाधिक विश्वसनीय है। *(दै.भा., 23.12.11 एवं न.ज़ु., 26.12.11)*

सर्वेक्षण के नतीजे

- *80 फीसदी से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार से निपटने के लिए चलाए जा रहे अभियान/कार्रवाई में भाग लेने को तैयार हैं।*
- *64 फीसदी भारतीय किसी न किसी वजह से पुलिस को रिश्वत देते हैं।*
- *63 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्होंने जमीन से जुड़े मामलों में रिश्वत दी। 62 फीसदी लोगों ने रजिस्ट्री और परमिट के लिए रिश्वत देने की बात मानी।*
- *55 फीसदी लोगों को लगता है कि देश की सरकार भ्रष्टाचार से प्रभावी तरीके से नहीं निपट पा रही है।*

भ्रष्टाचारः हम आठ कदम और आगे

वर्ष 2011 में पिछले साल के मुकाबले भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसी साल देश में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आन्दोलन भी देखा है। दुनिया में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक देश की छवि तीन साल से लगातार गिर रही है।

संस्था ने 183 देशों को अपनी सूची में शामिल किया है। इन देशों को शून्य से 10 के स्केल पर नंबर दिए गए। भारत को सिर्फ 3.1 अंक मिले हैं। जबकि उसे पिछले साल 3.3 अंक मिले थे। तब हम भ्रष्टाचार में 47वें स्थान पर थे। इस बार लुढ़ककर 95वें नम्बर पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड में सबसे कम भ्रष्टाचार है उसे 10 में से 9.9 नम्बर मिले हैं। इसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और सिंगापुर आता है। इन्हें क्रमश 10 में से 9.4, 9.4, 9.3 और 9.2 नम्बर मिले हैं। *(दै.भा., 02.12.11)*

हाईकोर्ट ने मांगा भ्रष्टाचार के मामलों का रिकॉर्ड

भ्रष्टाचार के मामलों में नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने पर सवाल उठाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं देने से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह टिप्पणी करते हुए ऐसे मामलों में कार्रवाई पर नौकरशाही की मानसिकता टटोलने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 15 साल से दर्ज मामलों का रिकॉर्ड मांगा है।

महाअधिवक्ता को यह रिकार्ड पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन - प्रथम की खण्डपीठ ने पूनम चन्द भंडारी की जनहित याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है। *(रा.प., 30.11.11)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
अजमेर	एम.एस.वर्मा	सहायक अभियन्ता, विद्युत निगम, सरवाड़	50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 01.10.11*
अलवर	कृष्णचन्द यादव	हैड कांस्टेबल, रैणी थाना, अलवर	1,000	*दै.भा., 04.10.11*
जोधपुर	डॉ. शांतिलाल	प्रभारी, रायपुर अस्पताल, पाली	600	*रा.प., 05.10.11*
बीकानेर	प्रेमरतन वाल्मीकि अब्दुल गफ्फार भाटी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर बिचौलिया	40,000	*रा.प. एवं दै.भा., 12.10.11*
भीलवाड़ा	शिवराज राव	एएसआई, कोतवाली थाना, भीलवाड़ा	4,000	*दै.भा., 14.10.11*
नागौर	चांद कंवर	पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जायल	10,000	*रा.प., 15.10.11*
झालावाड़	रमेश चन्द	व.लि., ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पिड़ावा	2,000	*रा.प., 15.10.11*
दौसा	गणपत लाल	लिपिक, रसद विभाग, दौसा	4,000	*रा.प., 19.10.11*
सीकर	रोहिताश मीणा	प्रबंधक वित्त, राजस्थान रोडवेज, सीकर आगार	5,000	*रा.प., 19.10.11*
उदयपुर	महेश कुमार ढाका	इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आयकर विभाग, उदयपुर	90,000	*दै.भा.एवं रा.प., 20.10.11*
हनुमानगढ़	के.आर.वर्मा	इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आयकर विभाग, हनुमानगढ़	50,000	*दै.भा.एवं रा.प., 20.10.11*
बीकानेर	हरिकिशन फुलवारिया	इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आयकर विभाग, बीकानेर	50,000	*दै.भा.एवं रा.प., 20.10.11*
झालावाड़	गोरधन लाल	कांस्टेबल, कनवाड़ा चौकी सदर थाना, झालावाड़	8,300	*रा.प., 21.10.11*
प्रतापगढ़	कालूलाल मीणा	हैल्पर, जेईएन कार्यालय, मुंगाणा बिजली निगम	3,000	*दै.भा.,22.10.11*
प्रतापगढ़	गोपाल गुर्जर	तकनीकी सहायक, विद्युत वितरण निगम	10,000	*रा.प., 24.10.11*
पाली	चूना राम विश्नोई मोहम्मद उमर	एसडीओ, रोहट उपखंड अधिकारी कार्यालय रीड़र, रोहट उपखंड अधिकारी कार्यालय	30,000	*रा.प. एवं दै.भा., 01.11.11*
जयपुर	मुरलीधर	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग	3,000	*दै.भा. एवं रा.प., 22.11.11*
उदयपुर	मनोहर लाल तुसावड़ा	उपनिदेशक, उद्यान विभाग, उदयपुर	10,000	*रा.प., 24.11.11*
सीकर	गिरधारी सिंह	सहायक उपनिरीक्षक, लाडनूं थाना	50,000	*रा.प., 26.11.11*
झुंझुनूं	कुरडा राम	पटवारी बदनगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू	10,000	*रा.प., 26.11.11*
श्रीगंगानगर	सत्यनारायण	व.लि., उपखंड अधिकारी कार्यालय, सादुलशहर	5,000	*रा.प., 03.12.11*
जयपुर	प्रदीप गोयल	थानाधिकारी, थाना कोटपूतली, जयपुर	50,000	*दै.भा.एवं रा.प., 10.12.11*
भीलवाड़ा	अनिल बांगड़ संदीप जैन	सहायक परियोजना समन्वयक, सर्वशिक्षा अभियान कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वशिक्षा अभियान	5,000	*रा.प., 14.12.11*
भीलवाड़ा	श्यामलाल भट्ट भैंरूलाल शर्मा	वनपाल, वन विभाग, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा वनरक्षक, वन विभाग, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	5,000	*रा.प., 18.12.11*
अलवर	रामकिशोर	कांस्टेबल, सम्मनवास पुलिस चौकी,नौगांवा	1,500	*रा.प., 18.12.11*
अजमेर	रतनलाल सोलंकी सोनाथ रेबारी	नायब तहसीलदार, उपतहसील कार्यालय, विजयनगर कार्यालय सहायक, उपतहसील कार्यालय, विजयनगर	33,000	*रा.प., 28.12.11*

खाद्य सुरक्षा बिल को मिली मंजूरी

महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से देश की 63.5 फीसदी आबादी को सस्ता अनाज प्राप्त करने की गांरटी मिलेगी। करीब 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी आबादी को इस योजना का फायदा मिलेगा। जरूरतमंदों को योजना के तहत गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए किलो की दर से मिलेगा।

इसके अलावा उन्हें अन्य खाद्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। जैसे गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषक आहार के साथ छह माह तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन दिया जाएगा। इस कानून के क्रियान्वयन पर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना में कृषि उत्पादन को भी तवज्जो दी जाएगी। *(दै.भा., 19.12.11)*

बीमारियों की कई जांचें होंगी निःशुल्क

प्रदेश में जननी-शिशु सुरक्षा और मुफ्त दवा योजना के बाद केन्द्र सरकार की ओर से अप्रेल माह से राजस्थान समेत पूरे देश के सभी सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर व कैंसर जैसी असंक्रामक बीमारियों की निःशुल्क जांच की व्यवस्था शुरू करना प्रस्तावित है।

फिलहाल यह योजना प्रदेश के दो जिलों अजमेर और भीलवाड़ा में चल रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और 30 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए सभी राज्यों से आंकड़े, जांच उपकरण तथा स्टाफ की जानकारी मांगी गई है। *(दै.भा., 26.11.11)*

जल्द लागू होगा सिटीजन चार्टर

केन्द्र सरकार ने निचले स्तर की नौकरशाही पर लगाम कसते हुए देश के नागरिकों की रोजमर्रा की शिकायतों का हल 15 दिन में कराने का कानूनी अधिकार देने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। सरकारी विभागों में लालफीताशाही व भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासन के हर विभाग में केन्द्र सरकार 'सिटीजन चार्टर' बनाने और उससे जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए क्रियाशील है। इससे नागरिकों के सरकारी विभागों में कार्य एक निर्धारित समय सीमा में हो सकेंगे और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

यह जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि नागरिक अधिकार विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। अन्ना हजारे ने भी इस चार्टर की मांग की थी।

(दै.भा. एवं रा.प., 03.11.11)

लागू होगी राशन टिकट व्यवस्था

प्रदेश में राशन सामग्री के लिए राशन टिकट व्यवस्था लागू की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले गेहूं, केरोसिन, आटा आदि का उठाव और वितरण निर्धारित समय पर होगा। उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ता सप्ताह के दौरान सभी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

प्रदेश के नए खाद्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने जिला रसद अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश देते हुए कहा है कि खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी हालत में सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि मिलावटी सामान पर रोक लगाने के लिए सीधे उत्पादनकर्ताओं से सैंपल लेकर कार्रवाई की जाए।

(दै.भा., 02.12.11)

मानवाधिकारों के प्रति लोग जागरूक बने

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मानवाधिकारों के संरक्षण व सामाजिक चेतना जागृत करने में मीडिया और स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं आम आदमी को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील, जागरूक और शिक्षित बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया की भूमिका को सभी स्वीकार करते हैं।

अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जयपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से 'मानवाधिकारों के संरक्षण में मीडिया एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका' पर आयोजित समूह चर्चा में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें प्रिन्ट मीडिया का महत्व ज्यादा है । आज भी अखबार में छपे शब्दों की विश्वसनीयता कायम है। ऐसे में जन शिक्षण के प्रभावी माध्यम के रूप में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। *(रा.प., 11.12.11)*

भारत की आधी आबादी गरीब

भारत की औसतन करीब आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यह लगभग 49 रुपए रोजाना से भी कम कमाई पर गुजारा करती है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

गरीबी के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो कारक तय किए हैं उनमें स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, खाना बनानें को ईंधन मिल पाना, घर में मूलभूत जरूरत की चीजें होना और घर के निर्माण का स्तर आदि शामिल किए गए हैं। इन सभी कारकों के आधार पर औसतन 41.6 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास यह सुविधाएं नहीं हैं।

(दै.भा., 03.11.11)

लोक सेवा गांरटी कानून प्रदेश में लागू

राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 14 नवम्बर 2011 से 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गांरटी अधिनियम-2011' लागू कर दिया गया है। इस कानून में आम लोगों के रोजाना काम पड़ने वाले 15 विभागों की 53 सेवाओं को शामिल किया गया है। और हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। 15 विभागों में ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, जन स्वास्थ्य, राजस्व, नगरीय विकास, आवासन, खाद्य, वित्त, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, जेडीए व यूआईटी विभाग शामिल है। इन विभागों की आम आदमी से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है।

आप सम्बन्धित विभाग से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस काम को करने के लिए कितने दिन की अवधि तय की गई है। आप अपने काम के लिए जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करे, उसकी रसीद प्राप्त करना आपका हक है। सम्बन्धित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नियत समय पर सेवाएं प्रदान नहीं करने पर उस पर 500 रुपए से 5 हजार रुपए तक की पैनल्टी लगाई जा सकेगी। इसके अलावा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान कानून में है। यदि आप कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो, आपको उस विभाग के अपील अधिकारी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। *(दै.भा. एवं रा. प., 14.11.11)*

खराब मीटर पर मिलेगी 5 फीसदी छूट

क्या आपका दो महीने से ज्यादा समय से बिजली का मीटर खराब है? बिजली कंपनी आपको औसत बिल थमा रही है, तो फिर क्या आपको हर बिल की राशि में 5 फीसदी छूट मिल रही है? यदि नहीं तो यह आपकी जागरूकता की कमी है। खराब मीटर नहीं

बदलने की स्थिति में नियमानुसार 5 फीसदी की छूट बिल में दी जानी चाहिए। लेकिन बिजली कंपनियां राज्य के 95 लाख उपभोक्ताओं में से 14 फीसदी को औसत बिल ही थमा रही है। उन्हें यह छूट नहीं दी जा रही और उपभोक्ता जानकारी के अभाव में ठगे जा रहे हैं।

इस बाबत मीडिया में खबर छापने पर ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि खराब मीटरों के न बदले जाने पर उपभोक्ताओं को पांच फीसदी छूट दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रदेश में लगभग 8 फीसदी मीटर खराब पड़े हैं।

(रा.प., 22.11.11, 25.11.11)

विद्युत कंपनियों को 7000 करोड़ का घाटा

देश की विद्युत वितरण कंपनियों को प्रति वर्ष 7000 करोड़ रुपए के नकद घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण इस क्षेत्र में समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है और कर्ज देने के नाम पर बैंकों की भी नींद हराम हो गई है। इक्विटी निवेशकों व विद्युत उत्पादन कंपनियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदेशों में भी राज्यस्तरीय बिजली कंपनियों का कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य पूरे बिजली क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके मद्देनजर राजस्थान सरकार ने बिजली कंपनियों को बैंकों से कर्जा दिलाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है जिसे राज्य मंत्रीमण्डल ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

(दै.भा., 25.10.11 एवं न.दु., 09.11.11)

सौर ऊर्जा में 10 हजाार करोड़ का निवेश

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत प्रदेश के रेगिस्तानी इलाके में 10 हजार करोड़ का निवेश होगा। केन्द्र के स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रियाओं में प्रदेश की 295 मेगावाट क्षमता की 24 परियोजनाओं का चयन हुआ है। जबकि अन्य राज्यों की 55 मेगावाट क्षमता की चार परियोजनाएं ही मंजूर हो सकीं।

अक्षय ऊर्जा निगम के तकनीकी निदेशक एम.एम. विजयवर्गीय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मिशन के तहत पूर्व में देश में स्वीकृत 750 मेगावाट की परियोजनाओं में से राज्य में 578 मेगावाट क्षमता की 48 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं और इन पर काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा सौर ऊर्जा नीति के तहत 43.5 मेगावाट की 9 परियोजनाओं का काम भी पूरा हो चुका है। सभी परियोजनाओं को मिलाकर राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में 10 हजार करोड़ का निवेश होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

(दै.भा., 06.12.11)

प्रदेश में है बिजली का कुप्रबंधन

केन्द्र सरकार ने बिजली कुप्रबंधन को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कर कहा है कि बिजली के मामले में वे खुद दखल करे और हालात सुधारें। इस पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज में राज्य के बिजली कुप्रबंधन का चिट्ठा भी लगा है।

पत्र में शिंदे ने बिजली कंपनियों की माली हालत पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि वे बिजली दरों के जरिए बिजली आपूर्ती का खर्चा भी वसूल नहीं कर पा रही है। यह भी साफ है कि कंपनियां बिजली छीजत रोकने में भी विफल साबित हो रही है और किसानों के पेटे बिजली की खपत दर्शाकर बचने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे को देखते हुए बैकों ने भी कर्ज देने से इन्कार कर दिया है।

(रा.प., 04.11.11)

बिजली उत्पादन में आएगी तेजी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 12 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन के प्रयास हो रहे हैं। यह क्षमता विकसित किए जाने की स्वीकृति जारी हो चुकी है। उन्होंने राज्यस्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने कहा कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा बायोमॉस ऊर्जा जैसे गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ इस क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग और इसकी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली औद्योगिक इकाइयों, राजकीय विभागों तथा जनसामान्य को सम्मानित किया।

(न.दु., 15.12.11)

बिजली चोरी और दुरुपयोग के मामले

जयपुर डिस्कॉम के सिटी सर्किल में चलाए अभियान में सतर्कता दलों की ओर से की गई जांच में 14 फीसदी कनेक्शनों में बिजली चोरी पाई गई। हर 20 कनेक्शनों में से 3 पर बिजली चोरी देख इंजीनियर भी चौंक गए। इसके साथ ही 86 फीसदी मामलों में बिजली का दुरुपयोग होता पाया गया।

शहर में 2696 स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर सतर्कता दलों ने 362 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी। इनकी पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके साथ ही 2334 मामलों में बिजली दुरुपयोग पाया गया। सिटी सर्किल के इंजीनियरों ने बिजली चोरी और दुरुपयोग पाए जाने पर एक करोड़ 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इनमें से 69 लाख रुपए के राजस्व मौके पर ही वसूल किए गए।

(दै.भा., 07.10.11)

बिजली अब हर साल देगी झटका

देश के सभी राज्यों की बिजली कंपनियों के लिए अब हर साल बिजली की दरें बढ़ानी अनिवार्य होंगी। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस वर्ष के शुरू में अपीलेंट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपटेल) को सिफारिशें भेजी थीं। इन पर गौर करने के बाद पिछले दिनों ट्रिब्यूनल ने देश के सभी राज्यों के नियामक आयोगों को हर साल खुद की मर्जी से बिजली की दरें बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

ऊर्जा मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल को लिखे पत्र में कहा था कि बिजली की कीमतों और आपूर्ति दरों में लगातार गहराती खाई के कारण ज्यादातर बिजली कंपनियों की हालत पतली होती जा रही है। फिर भी देश के नियामक आयोग बिजली एक्ट 2003 के अनुसार बिजली की दरें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया है।

(रा.प., 07.12.11)

कृषि कनेक्शनों पर लगा ब्रेक

बिजली की मांग और आपूर्ति के संतुलन में विफल साबित हो रही बिजली कम्पनियों ने अब कृषि कनेक्शनों पर अघोषित 'ब्रेक' लगा रखा है। प्रदेश में कनेक्शनों के लिए 73 हजार से भी ज्यादा किसान डिमाण्ड नोट जमा करा चुके, जिसके विपरीत कछुआ चाल से करीब 15 हजार कनेक्शन ही जारी किए गए हैं। इसके लिए ट्रांसफार्मर, मीटर, तार समेत अन्य विद्युत उपकरणों की कमी का कारण बताया जा रहा है।

(रा.प., 29.12.11)

मार्च तक बनेगी राष्ट्रीय जलनीति

केन्द्रीय जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि मार्च, 2012 तक राष्ट्रीय जलनीति को कैबिनेट में रख दिया जाएगा। इसमें पानी का बेहतर उपयोग और जल प्रबंधन को लेकर सभी प्रावधान शामिल होंगे।

जयपुर में आयोजित औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपयोग क्षमता पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उदघाटन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय जलनीति को लेकर राज्यों के साथ चर्चा की जा रही है। राज्यों की राय के बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। भूजल स्त्रोतों और पानी के बेहतर उपयोग को लेकर विशेष प्रयास करने की जरूरत बताते हुए जल आपूर्ति प्रबंधन, पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचना सहित कई समस्याएं है जिनका समाधान करना होगा। इसमें औद्योगिक क्षेत्र को भी पहल करनी होगी। *(दै.भा. एवं न.नु., 10.11.11)*

अच्छी क्वालिटी के मीटर लगेंगे

जलदाय विभाग जयपुर शहर में अच्छी क्वालिटी और लम्बे समय तक चलने वाले मीटर लगाएगा। इन मीटरों को बदलने का काम भी विभाग के कर्मचारियों से ही करवाया जाएगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट वाले इलाकों में ऑटोमेटिक मीटर रिडिंग वाले महंगे मीटर लगाने का विचार किया गया था।

अब विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि फिलहाल ऑटोमेटिक मीटर रिडिंग जैसे काफी महंगे मीटर लगाने का इरादा नहीं है। जलदाय व ऊर्जा मंत्री जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में सभी पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गई।

(दै.भा., 27.11.11 एवं रा.प., 01.12.11)

रेगिस्तान के नीचे है अथाह पानी

भले ही राजस्थान में पानी की कमी हो, लेकिन जमीन के नीचे अथाह जलधारा दौड़ रही है। इस जलधारा को जमीन की सतह तक जिस दिन लाया गया, उस दिन से पानी की किल्लत छूमंतर हो जाएगी।

देश के विख्यात ज्योलोजिस्ट डॉ. के. एस. वाल्दिया ने ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित व्याख्यान में यह जानकारी दी। डॉ. वाल्दिया ने बताया कि श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर के हिस्से में चट्टानों की गहराइयों में पेलियो चैनल्स या जलधाराएं बह रही है। एक-एक जलधारा इतनी लम्बी और चौड़ी है कि पानी जमीन पर लाया जाए तो खत्म ही नहीं होगा। दरअसल ये विलुप्त सरस्वती नदी की अवशेष हैं और आज भी हिमालय से जुड़ी हैं।

(रा.प., 22.11.11)

पानी की दरें बढ़ाने का विचार नहीं

पीएचईडी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि फिलहाल पानी की दरें बढ़ाने का न तो कोई विचार है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि लोगों को शुद्ध पानी मिले विभाग इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। फ्लोराइड युक्त पानी वाले क्षेत्रों के लिए सरकार विशेष योजना तैयार कर रही है और ऐसे कामों को लिए फंड की कोई कमी नहीं आने देगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए गांवों में सार्वजनिक स्थलों, आंगनबाड़ी, सरकारी भवनों और अन्य स्थलों पर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। गांवों में टांका निर्माण के काम को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। *(दै.भा., 13.12.11)*

कौन रोकेगा पानी की चोरी?

पानी के पैसे चुकाने वाले उपभोक्ताओं को प्रेशर से पानी नहीं मिलता और राइजिंग लाइनों से चौबीसों घंटे अवैध कनेक्शन कर लोग पेयजल की चोरी कर रहे हैं। रोजाना करीब 500 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी चोरी होता है लेकिन आज तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

हाल यह है कि जलदाय विभाग में पानी चोरों को पकड़ने के लिए एक्ट व स्टाफ का प्रावधान ही नहीं है। अवैध कनेक्शन पकड़े जाने पर केवल कनेक्शन हटाने की औपचारिकता ही की जाती है। ऐसे में कुल सप्लाई का 30 फीसदी से भी ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। *(दै.भा., 30.10.11)*

गांव-ढाणियों के लिए चाहिए फंड

पेयजल की किल्लत से जूझ रहे राजस्थान ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की तर्ज पर फंड उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई है। राज्य सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार किए एप्रोच पेपर में पेयजल संबधी मुद्दों पर मांगी गई राय में यह सुझाव देते हुए कहा है कि फ्लोराइड, खारे पानी, और नाइट्रेट की मात्रा वाले पानी की समस्या प्रदेश के हर जिले में हैं। इससे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और भरतपुर जिले ज्यादा प्रभावित है।

इस समस्या से प्रभावित 90 फीसदी गांव-ढाणियां इन्हीं जिलों में है। प्रदेश में प्रभावित इन 34,000 गांव-ढाणियों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है।

(दै.भा., 23.10.11)

पेयजल के लिए चाहिए 600 करोड़

राज्य सरकार जयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में सातों दिन 24 घंटे पेयजल सप्लाई शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जयपुर में इसके लिए मालवीय नगर और मानसरोवर में पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है।

प्रदेश की पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग व ऋण देने वाली विदेशी संस्थाओं जाइका और एशियन डवलपमेंट बैंक ने ऋण देने के लिए 24 घंटे पेयजल सप्लाई की शर्त भी लगा दी है।

इस व्यवस्था को जयपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में लागू करने के लिए जल संसाधन विभाग को 600 से 700 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामलुभाया ने बताया कि जयपुर में दो स्थानों पर किए जा रहे परीक्षण के अच्छे परिणाम आने लगे हैं।

(रा.प.एवं दै.भा., 15.11.11)

साफ पानी शहर की पहली जरूरत

जयपुर को अगर वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे चौबीस घंटे शुद्ध जलापूर्ति होती रहे व उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आए। शहर के आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो साफ पेयजल से भी महरूम हैं। पानी सीमित संसाधन है। जलदाय विभाग के पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर के चलते इसका 30 फीसदी हिस्सा छीजत में चला जाता है।

पानी की कमी को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को बचाने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग को पूरी तवज्जो दी जाए। शहर की पुरानी और जर्जर पेयजल लाइनों को बदला जाए जिससे दूषित पानी की समस्या से निपटा जा सके। पानी के मामले में प्रदेश को खास दर्जा दिया जाकर केन्द्र सरकार सहयोग करे व इसके लिए बजट में वृद्धि की जाए ताकि समस्या से निपटा जा सके। *(दै.भा., 25.12.11)*

महिला अधिकारों पर अभियान

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने बताया है कि महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी देने के लिए देशभर में अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमूमन रूप से यह देखा गया है कि अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने और जागरूकता के अभाव में महिलाओं को कई क्षेत्रों में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

प्रथम चरण में यह अभियान देश के चार राज्यों राजस्थान, केरल, पंजाब व उत्तरांचल में शुरू होगा। इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारियां देकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी कोटा में जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में पूर्व छात्रसंघ परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी।

(दै.भा., 19.11.11)

महिला जनप्रतिनिधियों का सशक्तिकरण

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा है कि पंचायतीराज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधियों लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के मार्फत ऐसे कार्यक्रम संचालित करने चाहिए, जिनसे उनके सशक्तिकरण के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बने। उन्हें सरपंचों और जागरूकता के लिए क्षेत्रीय भाषा में कार्यप्रणाली विकसित करनी होगी।

उन्होंने यह विचार पंचायतीराज व्यवस्था में महिला जन प्रतिनिधियों की सुदृढ़ता और चुनौतियों के मूल्यांकन पर शिवचरण माथुर शोध संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण परिणामों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाडकुमारी जैन ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की कमी से ग्रामीण इलाकों में सुधार नहीं हो पाया। उन्होंने कहा स्वयंसेवी संस्थाएं जागरूकता कार्यक्रम चलाकर इसमें सुधार ला सकती हैं।

(दै.भा., 06.12.11)

बालिका संबल योजना में अजमेर अव्वल

अजमेर जिले की माताओं ने सभी पुरानी परम्पराओं को तोड़कर बेटियों को प्यार देने के मामले में राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया है। एक तरफ जहां बेटियों को बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है और उनके भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे में राज्य की बेटियों से भेद नहीं करने के मामले में अजमेर ने प्रदेश में एक नई पहल की है।

बालिका संबल योजना में दो बेटियों के बाद बेटे का मोह त्यागकर परिवार नियोजन अपनाने में अजमेर की माताओं ने नई मिसाल गढ़ी है। जनगणना 2011 के मुताबिक अजमेर सहित प्रदेश के पांच जिलों जैसलमेर, भरतपुर, झालावाड़ और धौलपुर में लिगांनुपात में सुधार दर्ज किया गया है, जिसमें अजमेर सबसे अव्वल रहा है। *(दै.भा., 07.11.11)*

बालिकाएं कम होना चिंताजनक

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने देश में बालिकाओं की कम हो रही संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सामाजिक कुरीतियों का दुष्परिणाम है। जनगणना 2011 के मुताबिक 0 से 6 साल के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात केवल 914 है। यह आजादी के बाद सबसे कम है। इस पर खासतौर से विचार करना होगा और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना होगा।

उन्होंने कहा कि गर्भ में लिंग परीक्षण की तकनीक के दुरुपयोग से बालिकाओं की बढ़ती भ्रूण हत्या इसके लिए जिम्मेदार है। घटते लिंगानुपात से सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है।

(दै.भा., 18.11.11)

निस्वार्थ सेवा भावना को मिला सम्मान

जयपुर निवासी श्रीमती स्नेहलता शर्मा को मानसिक रूप से विमंदित एवं निःशक्तजन बच्चों के हित में सेवा भावना से काम करने, अध्यापन करने और अपने ससुर दीन दयाल शर्मा (पूर्व सैनिक और 1965 के युद्ध में 2 मेडल प्राप्त) जो कि डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित होने के कारण कौमा में चले गए, उनकी समर्पित भाव से सेवा की। उनके द्वारा किए गए ऐसे सराहनीय कार्यों के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, नई दिल्ली द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर केसरी हाउस वाईफ वुमैन अवार्ड 2011 से सम्मानित किया है। सराहनीय यह है कि देशभर में प्राप्त वोट के आधार पर 80263 प्रविष्ठियों में से अवार्ड के लिए चुनी गई मात्र 49 हस्तियों, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता किरन बेदी, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, गायिका सुगन्धा मिश्रा और पंजाबी लोकगीत गायिका बलविन्दर कौर आदि में उनका नाम है।

बीमारियों में हुआ इजाफा

महिलाओं की औसत आयु 65 से बढ़कर 71 हो गई है, लेकिन इनमें होने वाली बीमारियों का अनुपात इससे कहीं बहुत अधिक बढ़ गया है। 40 वर्ष की आयु से अधिक की महिलाओं की बीमारी में सौ फीसदी से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। खासतौर पर मेटाबोलिक सिंड्रोम जिसमें ओबेसिटी, शुगर, हार्टअटेक, हाइपरटेंशन, एल्जाइमर आदि के मामले आते हैं।

हाल ही वाशिंगटन में हुई नार्थ अमेरिकन इंटरनेशनल कोलेशन ऑफ मेनोपॉज आर्गेनाइजेशन (निकोमो) की बैठक में जयपुर की गायनेकोलाजिस्ट डॉ. सुनिला खंडेलवाल ने अपना शोध प्रस्तुत करते हुए कहा कि अगर महिलाएं खुद स्वस्थ रहें तो उनके बच्चे न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि वह अन्य बच्चों से ज्यादा होशियार अर्थात इंटेलिजेंट होंगे।

(दै.भा., 05.10.11)

विधवाएं कर सकेंगी सरकारी खर्च पर बीएड

राज्य में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं सरकारी खर्च पर बीएड या बीएसटीसी कर सकेंगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन का प्रारूप जारी कर दिया है। पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के आवेदन निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार करवा कर स्वीकृति के लिए निदेशालय भिजवाने होंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण ने इसके लिए सभी उपनिदेशक व जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रारूप भेज कर सभी कॉलेजों तक इसकी सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ प्रशिक्षित कार्मिक को ही अध्यापक पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। योजना का लाभ पाने के लिए वह सभी विधवा व परित्यक्ता महिलाएं पात्र मानी गई हैं जो वर्ष 2011-12 एवं इसके आगामी वर्षों में राज्य के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएसटीसी या बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगी।

(दै.भा., 23.10.11)

भ्रूण हत्या का कारण है दहेज

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश पी. सदाशिवम ने कहा है कि पढ़े-लिखे और धनवान होने के कारण इज्जतदार कहलाने वाले लोग शादी के लिए दहेज मांगते हैं, इसलिए जन्म लेते ही अब भी लड़कियां मारी जाती हैं। उन्होंने लैंगिक न्याय को किस्सा और महिला शोषण को एक सच्चाई बताया। भ्रूणहत्या में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है।

न्यायाधीश सदाशिवम ने यह सच्चाई जयपुर में राजस्थान बार कौंसिल द्वारा आयोजित '21वीं सदी में लैंगिक समानता' विषय पर अध्यक्षीय उद्‌बोधन में बयां की। उन्होंने कहा महिला से मायके और ससुराल दोनों जगह भेदभाव होता है। उन्होंने समाज सुधार में दक्षिणी भारत को अग्रणी बताते हुए कहा कि महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक आजादी एवं उनके अधिकारों को तवज्जो मिले तो कुरीतियां मिटाना दूर की कौड़ी नहीं रहेगा।

(रा.प.एवं दै.भा., 11.12.11)

दूरसंचार सेवाएं

मोबाइल कंपनियां बेहतर सुविधा दें

टेलीकॉम रेगूलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के सहयोग से सीकर जिले में कट्स एवं श्री चालराय शिक्षा समिति, पाटोदा के संयुक्त तत्वावधान में 17 दिसम्बर 2011 को जिला स्तरीय टेलीकॉम कंज्यूमर ऐजुकेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि जिला उपभोक्ता मंच की सदस्या श्रीमती इन्द्रा चौधरी ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दें तथा उपभोक्ता किसी प्रकार की शिकायत होने पर ट्राई को लिखित में शिकायत करें। कार्यशाला के प्रारंभ में कट्स के कार्यक्रम अधिकारी दीपक सक्सेना ने ट्राई की कार्यप्रणाली की विस्त्रत जानकारी दी। कार्यशाला में विभिन्न टेलीकॉम व मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे और उन्होंने अपनी सेवाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

इस अवधि में 30 दिसम्बर 2011 को दूसरी कार्यशाला चित्तौड़गढ़ में आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत दूरसंचार निगम लि. के जिला दूरसंचार प्रबंधक महेश मीणा ने बदलते प्ररिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को अत्यधिक जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता पर बल दिया और सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए हर तीन माह में चौपाल लगाने सुझाव रखा।

कार्यशाला के प्रारंभ में कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ के समन्वयक धर्मवीर यादव ने प्रतिभागियों को शिकायत निवारण प्रक्रिया और ट्राई की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। यहां भी कार्यशाला में विभिन्न टेलीकॉम व मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे और उन्होंने अपनी सेवाओं की जानकारी दी।

मानक सेवाएं

कहीं नकली तो नहीं जेवर !

पूरी दुनिया में जेवरात के लिए प्रसिद्ध जयपुर में हालमार्किंग सर्टिफिकेट मात्र सवा फीसदी ज्वैलर्स के पास है। भारतीय स्टेण्डर्ड नियमों के अनुसार बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी नकली या खोटी हो सकती है। जयपुर में अनुमानतः पांच हजार सोने और तीन हजार चांदी की ज्वैलरी की दुकानें हैं। इनमें से ज्यादातर के पास हालमार्किंग सर्टिफिकेट नहीं है। स्थिति यह है कि भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफाइड प्रतिष्ठान भी अपने यहां तैयार ज्वैलरी की जांच कराने में कोताही बरतते हैं। प्रयोगशालाओं को 48 घंटे में जेवरात की रिपोर्ट देने का अधिकार है लेकिन काम इतना कम है कि मात्र 20 घंटे में ही ज्वैलरी की रिपोर्ट दे दी जाती है। अतः खरीददारी करने से पहले जेवर पर हॉलमार्किंग का निशान जरूर देंखे।

सोने के जेवरों पर भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह, शुद्धता का नम्बर जैसे 22 केरेट के लिए 916, शुद्धता केन्द्र का मार्क, जेवर की दुकान का निशान और हॉलमार्किंग का निशान बहुत बारीक अक्षरों में लिखा होता है। दुकानदार से इन निशानों को देखने के लिए मैग्रिफाइंग ग्लास मांगे और उक्त पांच निशान देखकर जेवर खरीदें। दुकानदार से खरीद की पक्की रसीद लेना न भूलें।

(रा.प., 18.10.11)

निवेशक शिक्षा

फर्जी कम्पनियों पर लगेगी लगाम

चाहे डीमेट एकाउन्ट हो या बैंक खाते, अब एक ही बार केवाईसी(नो योअर कस्टमर) की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए जल्द ही रिजर्व बैंक नई प्रणाली लागू करने वाला है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सिन्हा ने जयपुर में आयोजित निवेशक शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अब किसी भी म्युचुअल, डीमेट या अन्य खाते में कोई लेनदेन हुआ है तो इसकी सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। निवेशकों की शिकायतें है कि उनके खाते से बिना बताए रकम निकल जाती है, ऐसे में यह व्यवस्था कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि पूंजी बाजार में फर्जी कम्पनियों की दस्तक से माहौल बिगड़ा है। ऐसी कम्पनियों पर लगाम लगाने के लिए सेबी प्रयासरत है और नए नियम बनाए जा रहे हैं। कम्पनियों को ग्राहक को अपना ट्रेक रिकॉर्ड बताना होगा। ट्रेडिंग एकाउन्ट खोलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

इस अवसर पर सिन्हा ने निवेशकों के लिए अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा की भी शुरूआत की। जिसका नम्बर 1800-22-7575 है। इस नम्बर पर सूचीबद्ध कम्पनियों, स्टाक दलालों, निवेश स्कीमों आदि से जुड़ी शिकायतें की जा सकती है। यह सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक काम करेगी।

(रा.प.एवं दै.भा., 31.12.11)

पर्यावरण

अपना स्वार्थ नहीं छोड़ रहे विकसित देश

अमेरिका में कैटरीना जैसे तूफानी चक्रवातों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। टापूओं पर बसे देश डूबने के कगार पर है। भारत में मानसून की स्थिति बदल रही है। यूरोप में हो रही तेज बर्फबारी से सभी आश्चर्यचकित हैं। इन सभी के पीछे ग्लोबल वार्मिंग और विकास के नाम पर बढ़ रहा कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके बावजूद डरबन सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के नाम पर सिर्फ चर्चाएं ही हुई इसे रोकने के लिए कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए।

सम्मेलन में इस पर नियंत्रण करने अथवा रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय अधिकतर विकसित देशों के प्रतिनिधि अड़ंगेबाजी करते नजर आए। क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार करने वाले देशों ने ही उसे नहीं माना। ज्यादा प्रदूषण करने वाले विकसित देश अपना स्वार्थ छोड़ना नहीं चाहते। सम्मेलन में यह भी बात उठी कि बड़े विकासशील देश भारत-चीन समसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। लेकिन विकास करने के तर्क के साथ वे उसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं। अमेरिका, कनाडा, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और न्यूजीलैण्ड के प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान सिर्फ अड़ंगेबाजी और सियासत करते नजर आए। *(दै.भा., 09.12.11)*

उपभोक्ता फैसले

बैंकिंग नहीं यह लूट है-बैंक दे आठ लाख का जुर्माना

वैशाली नगर में रहने वाले डॉ.आलोक सक्सेना ने उपभोक्ता मंच, जयपुर में आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ अपने वकील के जरिए परिवाद दायर किया। उन्होंने परिवाद में मंच को जानकारी देते हुए बताया कि उसने 2006 में बैंक से 5 लाख 25 हजार रुपए का ऋण लिया था। कुछ किश्तें देने के बाद उन्होंने पूरे ऋण की अदायगी के लिए 4 लाख 99 हजार 769 रुपए बैंक को चुकाकर पूरा भुगतान प्राप्त करने की रसीद ले ली थी। इसके बाद भी बैंक ने उनपर 56 हजार 414 रुपए बकाया निकाल दिए। इसके बाद बैंक की ओर से धमकी भरे फोन भी आने लगे। यहां तक कि उनका नाम क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो लि.की ब्लैक लिस्ट में भी दर्ज करा दिया।

मामले की सुनवाई पर बैंक अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि बकाया रकम किस बात के लिए ली जा रही है। मंच ने पूरा हिसाब-किताब लगाया तो पाया कि बैंक का रवैया उपभोक्ता को धोखा देने जैसा है। बैंक की इस करतूत को मंच ने लूट करार दिया। उपभोक्ता मंच ने परिवादी पर निकाले बकाया 56 हजार 414 रुपए निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटाने का आदेश दिया। मंच ने बैंक पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसमें से एक लाख रुपए परिवादी को अदा करने होंगे और 7 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने होंगे। इसके अलावा बैंक को परिवादी की ओर से जमा कराई अधिक राशि पर आठ माह का ब्याज देने और परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए भी अदा करने के आदेश मंच द्वारा दिए गए हैं। *(रा.प., 12.12.11)*

वीडियोकॉन कम्पनी इनाम में निकला सोना दे

डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा की रहने वाली नीलम ने वर्ष 2003 में 12 हजार 700 रुपए में वीडियोकॉन कम्पनी का फ्रिज व वाशिंग मशीन खरीदी थी। कम्पनी की इनामी योजना के तहत उसे दो स्क्रेच कार्ड दिए गए। इसमें से एक कार्ड में 5 किलो सोना और दूसरे में अन्य उत्पाद की खरीद पर 50 फीसदी छूट का इनाम निकला। लेकिन कम्पनी ने फर्जी कार्ड बताते हुए ईनाम देने से मना कर दिया। नीलम ने अपने पिता के मार्फत राज्य उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।

सुनवाई पर कम्पनी अपनी दलील में स्केच कार्ड को फर्जी सिद्ध नहीं कर सकी। इस पर आयोग के पीठासीन सदस्य शशि कुमार पारीक व सदस्य लियाकत अली ने कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी माना और कहा कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आयोग ने कम्पनी को दो माह में 5 किलो सोना अथवा खरीद की तिथि के बाजार भाव से 36 लाख रुपए 12 फीसदी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। फैसले के अनुसार कम्पनी को इसके अलावा नीलम की मानसिक परेशानी के एवज में एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और परिवाद खर्च के 20 हजार रुपए और देने होंगे। *(रा.प., 22.10.11)*

खास समाचार

बिजली कनेक्शन भी नागरिक की मूल आवश्यकता

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त हवा और विधिक जागरूकता के बाद अब न्यायालय ने बिजली को भी नागरिकों की मूल आवश्यकता की श्रेणी में मान लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चार साल से बिजली कनेक्शन नहीं मिलने के मामले में यह फैसला सुनाते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

न्यायालय ने सीताराम की इस याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि दो भाइयों के बीच सिविल दावा चलने के आधार पर बिजली कनेक्शन नहीं देना बेहद गलत है। न्यायालय ने विद्युत निगम को निर्देश दिया कि चार साल से लम्बित प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर मौजूदा निर्धारित राशि जमा कर 15 दिन में कनेक्शन जारी कर दिया जाए। न्यायालय ने प्रार्थी को विद्युत कम्पनी पर उसका दायित्व पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने की छूट भी दी है। *(रा.प., 19.11.11)*

क्यों हैं उपभोक्ता मंचों में पद खाली?

देश के कई राज्यों में आज भी उपभोक्ता न्यायालय बहुत अधिक सक्रिय नहीं हैं। इससे उपभोक्ताओं को जल्दी न्याय नहीं मिल पाता। विभिन्न राज्यों के उपभोक्ता आयोगों में काफी समय से करीब 42 अध्यक्षों और 238 सदस्यों के पद रिक्त पड़े है।

राज्य सरकारों द्वारा जिला उपभोक्ता मंचों में सदस्यों व अध्यक्षों के रिक्त स्थान नहीं भरे जाने के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को न्याय के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है।

केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्री के.वी. थामस भी इससे वाकिफ हैं। उन्होंने खुद राज्य सरकारों से कहा है कि उच्च गुणवत्ता के नागरिकों का चयन कर उपभोक्ता मंचों को पूरी तरह सक्रिय करें। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें रिक्त पदों को नहीं भरती है तो केन्द्र सरकार को इसके लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है तथा खाली स्थानों को भरने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। *(न.नु., 10.11.11)*

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से किया सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए जाते रहे हैं। यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने जनहित के मामलों को पत्रकारिता के माध्यम से असरदार तरीके से उठाया है। इस बार का यह पुरस्कार 29 नवम्बर, 2011 को 'कट्स'द्वारा ग्रेनिर्का परियोजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोडा के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

उन्होंने वर्ष 2010 के लिए चयनित 'भ्रष्टाचार' विषय पर की गई उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए स्वतन्त्र पत्रकार लक्ष्मी लाल सालवी (लखन सालवी) को पुरस्कार स्वरूप 10 हजार रुपए की राशि का चैक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

स्त्रोतः रा. प.ः राजस्थान पत्रिका, दै. भा.ः दैनिक भास्कर, न. नु.ः नफा नुकसान, दै. न.: दैनिक नवज्योति

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।